भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

02.08.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2199 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों का पुनर्विकास

2199. श्रीमती प्रतिभा सिंह:

श्री चंद्र शेखर साहू:

सुश्री सुनीता दुग्गल:

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

श्री रामदास तडस:

श्री के. मुरलीधरन:

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

श्रीमती जसकौर मीना:

श्री के. सुधाकरन:

श्री घनश्याम सिंह लोधी:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने दिसम्बर, 2022 में देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) मास्टर प्लान में इस योजना के अंतर्गत चयनित स्टेशनों में विकसित की जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु के स्टेशनों, उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के बिलासपुर स्टेशन, महाराष्ट्र के धाराशिव के बार्शी स्टेशन, मध्य प्रदेश के शहडोल, केरल के कन्नूर और हरियाणा के सिरसा स्टेशनों का चयन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इसे निजी सार्वजनिक भागीदारी के अंतर्गत किया जाना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए स्टेशनों में स्टेशन-आधारित आवश्यकता के अतिरिक्त कोई सार्वभौमिक अवसंरचना अद्यतन करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार द्वारा कांगड़ा वैली नैरो गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में दिनांक 02.08.2023 को लोक सभा मे श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री चंद्र शेखर साहू, सुश्री सुनीता दुग्गल, श्री ओम पवन राजेनिंबालकर, श्री रामदास तडस, श्री के. मुरलीधरन, डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्रीमती जसकौर मीना, श्री के. सुधाकरन, श्री घनश्याम सिंह लोधी, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और श्रीमती हिमाद्री सिंह के अतारांकित प्रश्न सं. 2199 के भाग (क) से (ज) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (छ): भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास के लिए हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इस योजना में प्रत्येक ऐसे स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशनों तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकता अनुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणालियों, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यापारिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और इन्हें विभिन्न चरणों में कार्यान्वित करना शामिल है।

इस योजना में स्टेशन इमारत में सुधार, शहर के दोनों छोर के साथ स्टेशन को जोड़ने, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेल पथ का प्रावधान, आवश्यकता के अनुसार 'रूफ प्लाज़ा' और लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर की चरणबद्ध योजना व व्यवहार्यता और निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

वर्तमान में, इस योजना के तहत उन्नयन/विकास के लिए भारतीय रेलों में 1309 स्टेशनों की परिकल्पना की गई है। प्रमुख शहरों और नगरों में स्थित स्टेशनों में से क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्टेशनों का चयन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चिह्नित स्टेशनों की राज्य-वार सूची परिशिष्ट में दी गई है।

मध्य प्रदेश राज्य में सहडोल, केरल राज्य में कन्नूर और हरियाणा राज्य में सिरसा इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किए गए हैं।

बजटीय निधि का उपयोग अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के विकास के लिए किया जा रहा है। बहरहाल, स्टेशनों की बहुत छोटी संख्या को सार्वजनिक निजि भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकास के लिए खोज किया जा रहा है।

स्टेशनों का आधुनिकीकरण/उन्न्यन एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकता के अनुसार शुरु की जाती हैं जो परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन होती है। कार्य की स्वीकृति और निष्पादन करते समय स्टेशनों के उन्न्यन/आधुनिकीकरण के लिए प्राथमिकता निम्नतर कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशनों को जी जाती है।

(ज): रेलवे परियोजनाएं क्षेत्रीय रेलों-वार स्वीकृत की जाती है न कि राज्य-वार/संसदीय क्षेत्र-वार/क्षेत्र-वार, क्योंकि ये राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। कांगड़ा घाटी में पठानकोट-जोगींदर नगर (172 किमी) आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण 2017-18 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की लागत 18686 करोड़ रू. थी। कम यातायात अनुमान के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है।

******

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में दिनांक 02.08.2023 को लोक सभा मे श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री चंद्र शेखर साहू, सुश्री सुनीता दुग्गल, श्री ओम पवन राजेनिंबालकर, श्री रामदास तडस, श्री के. मुरलीधरन, डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्रीमती जसकौर मीना, श्री के. सुधाकरन, श्री घनश्याम सिंह लोधी, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और श्रीमती हिमाद्री सिंह के अतारांकित प्रश्न सं. 2199 के भाग (क) से (ज) के उत्तर से संबंधित ब्यौरा का परिशिष्ट।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या :-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चिह्नित स्टेशनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	72
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	50
4	बिहार	92
5	छत्तीसगढ़	32
6	दिल्ली	13
7	गोवा	3

8	गुजरात	87
9	हरियाणा	34
10	हिमाचल प्रदेश	4
11	झारखंड	57
12	कर्नाटक	56
13	केरल	35
14	मध्य प्रदेश	80
15	महाराष्ट्र	126
16	मणिपुर	1
17	मेघालय	1
18	मिजोरम	1
19	नागालैंड	1
20	ओडिशा	57
21	पंजाब	30
22	राजस्थान	83

23	सिक्किम	1
24	तमिलनाडु	75
25	तेलंगाना	40
26	त्रिपुरा	4
27	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	1
28	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	4
29	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	3
30	उत्तर प्रदेश	156
31	उत्तराखंड	11
32	पश्चिम बंगाल	98

******